RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.c swarajindi- swarajindi-

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

मूल्यः ` 02

कानपुर,मंगलवार , 16 सितंबर 2025
वर्षः 02, अंकः 243, पृष्ठः 8+4

गाजीपुर प्रकरणः थाने में पिटाई से गई भाजपा कार्यकर्ता की जान, नहीं मिला न्याय सीएम से मिले परिजन

इनसाइड स्कूल वालों ने हमाई बिटिया को मार डाला...! » Pg 10

» Pg12

हमीरपुरः फर्जी मुकदमे में जेल गए युवक की पीटकर हत्या

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हमीरपुर। जिले में एक चौंकाने वाली घटना ने प्रशासन से लेकर जनता तक को हिला दिया है। फर्जी एस्ट/स्ज्ज एक्ट के मुकदमे में जेल भेजे गए अनिल उर्फ अमित द्विवेदी की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है।

» घटना के बाद बवाल, कई जेल अधिकारी निलंबित, हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग तेज

दिल्ली में अपने पिता श्रीकृष्ण द्विवेदी के साथ गार्ड की नौकरी करने वाले अमित द्विवेदी पर हमीरपुर में एस्ट/स्ज्ञ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों का कहना है कि यह मुकदमा पूरी तरह फर्जी था। कोर्ट की तारीखों पर अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। 10 सितंबर को वे दिल्ली से घर आए और 11 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के बाद जेल भेज दिए गए।

झ्रमुलाकात के बाद मौत की खबर

12 सितंबर को उनकी पत्नी पूजा तिवारी जेल में मुलाकात करने गईं और खर्चे के लिए ?6500 भी दिए। अगले दिन रिश्तेदार राहुल पांडेय ने परिजनों को बताया कि अमित की तबीयत बिगड़ गई है। जब 13 सितंबर को पत्नी फिर मिलने गईं तो जेल प्रशासन ने उन्हें

शरीर में चोटों के निशान दिखाते घर वाले

मुलाकात नहीं करने दी। उसी दिन दोपहर बाद अचानक प्रशासन ने अमित की मौत की सूचना दी।

शव पर चोटों के निशान, सड़क पर विरोध

परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन पहले शव को सीधे पोस्टमार्टम हाउस भेजना चाहता था। लेकिन परिवार और ग्रामीणों के विरोध पर शव को

दिखाया गया, जहां मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान स्पष्ट दिखाई दिए। इससे आक्रोश फैल गया और लोगों ने जेल गेट पर सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

जेल अधिकारियों पर गिरी गाज

घटना के बाद उच्च स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मृतक के परिजन अब संबंधित जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए है।

परिवार का कहना है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि जेल में की गई हत्या है। फर्जी मुकदमे में फँसाकर एक गरीब ब्राह्मण परिवार को तबाह कर दिया गया और एक नवविवाहिता को विधवा बना दिया गया ।फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं इस घटना ने पूरे जिले में आक्रोश और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है।

सेवारत शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मिलेगी राहत

» योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी रिवीजन

» मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य कर दिया गया था।

सीएम योगी का मानना है कि वर्षों से सेवाएं दे रहे और नियमित प्रशिक्षण पा रहे शिक्षकों के अनुभव को केवल एक परीक्षा के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।

उन्होंने साफ कहा कि ऐसे अनुभवी शिक्षकों की योग्यता और योगदान को सम्मान मिलना चाहिए, न कि नौकरी पर संकट।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि नौकरी में बने

रहने के लिए हर शिक्षक को टीईटी पास करना होगा।

इससे लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था और उनमें भय का माहौल बन गया था।

योगी सरकार का यह कदम शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने वाला है और उनके वर्षों की मेहनत और अनुभव को मान्यता देने वाला है।सरकार की नरमी से आगे की राह खुली

बेसिक शिक्षा विभाग अब सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेगा, जिसमें यह तर्क दिया जाएगा कि अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। अगर कोर्ट सरकार की दलीलें मान लेता है तो लाखों शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत मिलेगी।

यह फैसला भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक नया अध्याय साबित हो सकता है। कुल मिलाकर, यह खबर प्रदेश के शिक्षकों के लिए सुकून और उम्मीद की बड़ी सौगात लेकर आई है।

कल होगा कानपुर विश्वविद्यालय का 40 वा दीक्षांत समारोह

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

59 पदक कुलाधिपति एक स्वर्ण , एक रजत और 30 कांस्य पदक किए जाएंगे वितरित

कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के 17 सितंबर को होने वाले दीक्षांत में 59 छात्रों को कुल 97 पदकों से सम्मानित किया जाएगा। जिसमें 45 पदक बेटियों को मिलेंगे। वहीं, 75 छात्रों को पीएचडी उपाधि दी जाएगी, जिसमें 50 बेटियां शामिल हैं। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। मुख्य अतिथि डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी रहेंगी। समारोह में जम्मू-कश्मीर की जाहिदा अमीन को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

यह जानकारी विवि के सेंटर फॉर एकेडमिक्स में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी व रजिस्ट्रार राकेश कुमार ने दी। प्रो. पाठक ने बताया कि विवि के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित दीक्षांत में 1,02,536 छात्र-छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। समारोह में विवि के 90.52 फीसदी अंक लाने वाली स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की छात्रा कोमल कमल को सर्वोच्च कुलाधिपति स्वर्ण समेत छह पदकों से सम्मानित किया जाएगा। वीएसएसडी कॉलेज की आराधना तिवारी और डीडब्ल्यूटी कॉलेज के जीत शर्मा को चार-चार पदक दिए जाएंगे। 23 छात्र-छात्राओं को दो या दो से अधिक पदक मिलेंगे। समारोह में कैम्पस के 13 और महाविद्यालयों के 46 छात्रों को पदक मिलेंगे। समारोह की शुरुआत राज्यपाल समेत सभी अतिथि सिंदूर पौधे को रोपण कर करेंगी।

फिर स्टार्टअप एक्सपो देखने के बाद 8 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और 4 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। विवि में छात्रों के लिए एआर-वीआर सिमुलेशन लैब की शुरुआत की जाएगी।

जिससे विवि कैम्पस के साथ बाहरी छात्र भी एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले फिजिक्स के प्रैक्टिकल वर्चुअल मोड पर कर सकेंगे।

महिलाओं के सशक्तिकरण में है जाहिदा का योगदान

प्रो. पाठक ने बताया कि साहित्य और समाज सेवा में योगदान के लिए जाहिदा अमीन को मानद उपाधि दी जाएगी। जाहिदा जम्मू-कश्मीर के बारामुला के सोपोर की रहने वाली हैं। उन्होंने पारंपरिक कश्मीरी शिल्प जैसे सोजनी कढ़ाई, कानी शॉल और पेपर माशे को संरक्षित करने एवं विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 10,000 से अधिक महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। उनके कार्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है।

11 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा

प्रो. पाठक ने बताया कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य, प्रबंधन, नवाचार, शोध, खेल, एआई, एनईपी विषयों से जुड़ी 11 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। सुपर कंप्यूटिंग हब फॉर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का शुभारंभ होगा। पांच नवाचार स्टार्टअप को सम्मानित किया जाएगा।

मियावाकी पद्धति से तैयार होगा जंगल

विवि में मियावाकी पद्धति से जंगल तैयार होगा। जिसमें 18 हजार पौधे लगाए जाएंगे। यह ऑक्सीजन जनरेटर का काम करेंगे। इसकी मदद से विवि और आसपास के इलाकों में एक-दो डिग्री तापमान में कमी आएगी।

इन शिक्षकों को मिलेगा सम्मान

विवि की रैंक और नैक ग्रेडिंग में मदद करने के साथ रिसर्च में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छह शिक्षकों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत में सम्मानित करेंगी।

ट्रेन की चपेट में आई युवती, धड़ ट्रैक पर

» सर तीस फीट दूर गिरा, पुलिस और जीआरपी शिनाख्त में जुटी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर । कल्याणपुर क्रॉसिंग पर मंगलवार दोपहर एक सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन की तेज रफ्तार से शव क्षत-विक्षत हो गया। पुलिस और जीआरपी शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।

कानपुर में कल्याणपुर क्रॉसिंग में मंगलवार दोपहर करीब एक बजे सुपरफास्ट गाड़ी की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। उसकी उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि शव धड़ बीच ट्रैक पर था, जबकि सर करीब तीस फीट दूर जा गिरा। ट्रेन की रफ्तार करीब सौ किलोमीटर प्रति घंटा की होगी।

हादसे की सूचना मिलते ही ट्रेन रोक दी गई। थाना पुलिस और जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। आसपास दुकानदारों के मुताबिक लड़की किसी दुकान में काम करती होगी। यह हादसा थाने से महज सौ कदम दूर हुआ है। ट्रेन कानपुर से दिल्ली जा रही थी। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।

नगर निगम ने 'स्वच्छता ही सेवा 2025' अभियान को बनाया जन-आंदोलन

» सुधारात्मक कार्यप्रणाली से शहर को मिलेगा स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर स्वरूप

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम कानपुर अपनी कार्यशैली और सुधारात्मक छवि के साथ लगातार शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सुधीर कुमार की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।

बैठक में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, सड़क या गली में गंदगी अथवा कूड़ा बिखरा न दिखे इसके लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी।

त्योहारों व जन-जागरूकता पर विशेष फोकस

आगामी त्योहारों को देखते हुए रामलीला समितियों से बैठक कर स्वच्छता पर विशेष योजना बनाई जाएगी। साथ ही, मीडिया व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक अभियान चलाकर शहरवासियों को जागरूक किया जाएगा।

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वयं भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें और कर्मचारियों की फेस टू फेस अटेंडेंस व नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

नगर निगम कानपुर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वच्छता ही सेवा 2025 सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा आंदोलन है। नगर निगम का प्रयास है कि शासन की मंशा और जनता के सहयोग से शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर कानपुर के रूप में पहचान दिलाई जा सके।

सुधार की दिशा में अहम निर्णय

- 100प्रति. डोर-टू-डोर कलेक्शन सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय
- खाली प्लॉट्स पर कूड़ा डालने वालों पर जुर्माना व वसूली की कार्यवाही
- 10 वार्ड्स को सैचुरेट मॉडल वार्ड बनाने की योजना
- स्कूलों में ब्यूटीफिकेशन व अवेयरनेस ड्राइव से बच्चों को जोड़ा जाएगा
- वेस्ट टू आर्ट (कचरे से कला) प्रोजेक्ट के तहत मूर्तियां व कलाकृतियां बनवाई जाएंगी
- बल्क वेस्ट जनरेटर्स की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध निस्तारण
- खाद्य सुरक्षा मानकों पर आधारित फूड स्ट्रीट का निर्माण
- आरडब्ल्यूए व सामाजिक संगठनों के सहयोग से सामुदायिक कम्पोस्टिंग को बढ़ावा

आरटीओ कार्यालय में दलालों की मिलीभगत बेनकाब

डीएम ने किया औचक निरीक्षण तो खुल गई पोल

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सर्वोदय नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में मंगलवार सुबह जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के औचक निरीक्षण ने व्यवस्था की पोल खोल दी। निरीक्षण में जहाँ सात कर्मचारी अनुपस्थित मिले, वहीं कार्यालय में सक्रिय दलालों का नेटवर्क भी उजागर हुआ।निरीक्षण के दौरान डीएम ने एक आवेदक अरविंद गौड़ से मोबाइल पर बात की। गौड़ ने बताया कि ई-रिक्शा की डुप्लीकेट आरसी दिलाने के लिए उसने एक प्राइवेट व्यक्ति को 2000 रुपये दिए, जबकि तय शुल्क केवल 500 रुपये है। डीएम ने जब उस प्राइवेट व्यक्ति से बात की तो पहले उसने रकम लेने से इनकार किया, लेकिन कड़ी पूछताछ में सच सामने आ गया और उसने दलाली स्वीकार कर ली।

जिलाधिकारी ने इस पर गहरी नाराज़गी जताई और डीटीसी को पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

सात कर्मचारी नदारद, वेतन काटने का आदेश

सुबह 10:35 बजे तक उपस्थिति पंजिका की जाँच में सात कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए—मधुबन मिश्रा, कमरूल इस्लाम, प्रीति तोमर, ऋषभ कुमार, शुभम सिंह, रतना यादव और चपरासी दिनेश कुशवाहा। डीएम ने इन सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि भविष्य में दोहराव हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी।

जनता की परेशानी, लंबित प्रकरणों पर नाराज़गी

निरीक्षण में पता चला कि सोमवार को करीब 300 लोग स्थायी लाइसेंस और नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए कार्यालय पहुँचे थे।

कई प्रकरण लंबित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

डीएम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट-6 आलोक गुप्ता को आरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा दिया। साथ ही एआरटीओ (प्रशासन) आलोक कुमार को परिसर की स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

बिल्हौर सपा में दावेदारी का घमासान, सोशल मीडिया पर नेताओं की जुबानी जंग

» अपनी अपनी टिकट के चक्कर में कहीं कोई और न मार ले जाए बाजी

» पार्टी के अनुशासन को ठेंगा दिखा रहे उमड़े तमाम दावेदार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। समाजवादी पार्टी में बिल्हौर विधानसभा सीट को लेकर अंदरुनी खींचतान सामने आ गई है। अब दावेदार सोशल मीडिया पर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को सपा नेत्री रचना सिंह ने फेसबुक पर कई वीडियो पोस्ट किए। वीडियो में वह सपाईयों के साथ नारेबाजी करती दिख रही हैं, लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि यह प्रदर्शन कहाँ हुआ। स्थान का उल्लेख न कर सस्पेंस बनाए रखने से पार्टी नेताओं के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरु हो गई हैं। इस बीच शाम होते ही अन्य दावेदार सक्रिय हुए और परोक्ष रुप से रचना सिंह को घेरते नजर आए।

अर्चना रावल द्वारा एफबी पर डाली गई पोस्ट

विनय कोरी ने ऐसे तंज कसा

बिल्हौर सीट से सपा से दावेदारी पेश कर रहे विनय कोरी ने फेसबुक पर लिखा। नक्कालों से सावधान कार्यकम कहीं और का पता बिल्हौर विधानसभा का। वहीं दूसरी दावेदार अर्चना रावल ने पोस्ट डाली कि बिल्हौर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का किसी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। दोनों पोस्ट से यह साफ हो गया है कि रचना सिंह के दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भले ही किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे उन्हीं पर हमला माना जा रहा है। बिल्हौर विधानसभा से सपा में कई चेहरे दावेदारी में सक्रिय हैं। और अब सोशल मीडिया पर शुरू हुई जुबानी जंग इस बात का सबूत है कि पार्टी के भीतर खींचतान कितनी गहरी है।

ये सपा के या भाजपा के?

बिल्हौर। रचना सिंह गौतम के पति पंकज यादव ने कहा कि बिल्हौर की आवाज लोग लखनऊ में उठाने चले जाते हैं। आवाज उठाने के लिए जगह, स्थान नहीं होता है। आप किसी भी क्षेत्र की आवाज कहीं से भी उठा सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सपा के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अधिकारियों का दिया गया प्रशिक्षण

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर कानपुर)। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम बिल्हौर संजीव दीक्षित के दिशा-निर्देशन में सोमवार को एसडीएम कार्यालय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।कार्यशाला में सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के उपरांत मुख्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को विस्तार से साझा किया गया। पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के निर्देशों पर आधारित प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभागियों ने गंभीरता से हिस्सा लिया। इस अवसर पर तहसीलदार बिल्हौर अनुभव चंद्रा, नायब तहसीलदार रंजीत कुमार यादव, खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर रवि कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी बिल्हौर बलराम सिंह एवं खंड विकास अधिकारी चौबेपुर विशेष रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता से कार्य करने का संकल्प लिया।

सम्पादकीय

दीर्घकालिक शांति की जाए सुनिश्चित

लंबे समय तक अशांत रहे मणिपुर के मुद्दे पर अकसर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। अब वह प्रतीक्षित यात्रा हकीकत बनी है। कहा जा सकता है कि संघर्षरत राज्य की जनता के बीच विश्वास की कमी को दूर करने का यह सार्थक प्रयास जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाने का संकल्प जताया है। लेकिन मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति सरकार के संकल्प की परीक्षा लेगी। हालांकि,लगभग ढाई साल पहले भड़की जातीय हिंसा हाल के महीनों में, खासकर फरवरी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कम हो गई है। लेकिन भविष्य में हिंसा की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता है।

ऐसी दशा में इस संवेदनशील राज्य में केंद्र सरकार को सामान्य स्थिति की बहाली और दीर्घकालिक शांति स्थापना के लिये हर संभव प्रयास करने चाहिए। दरअसल,राज्य में स्थायी शांति के मार्ग में जो एक सबसे बड़ी बाधा है, वह है पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय और घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों के बीच लगातार कम होता विश्वास। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि दोनों समुदायों की आकांक्षाओं में संतुलन बनाए। ताकि दोनों समुदायों की चिंता और शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जा सके। विगत में मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग करते रहे हैं। यह एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा था, जिसने कुकी–जो समुदाय के लोगों में असुरक्षा व अशांति पैदा कर दी। जिसे दूर किए जाने की सख्त जरूरत है।

दरअसल, हाल के हिंसक संघर्ष ने राज्य में मतभेदों को मनभेद में बदल दिया है। कुकी–जो विधायकों के एक समूह, जिसमें भाजपा के भी सात विधायक शामिल हैं, ने कहा है कि 'दोनों पक्ष केवल अच्छे पड़ोसियों के रूप में शांति से रह सकते हैं,लेकिन फिर कभी एक छत के नीचे नहीं।' उनकी मांग रही है कि गैर–मैतेई समुदायों के लिये अलग विधायिका सहित अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए। यह सोच दोनों समुदायों के बीच गहरे मतभेद को उजागर करती है, जिसने मणिपुर को गहरी क्षति पहुंचायी है। इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव होने में अभी डेढ़ साल बाकी है। राज्य में हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है ताकि विधानसभा चुनाव में देरी न हो।

केंद्र सरकार को विधानसभा को लंबे समय तक निलंबित रखने के फायदे और नुकसान का भी आकलन करना होगा। लेकिन फिलहाल, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर देने की जरूरत है। उससे भी महत्वपूर्ण, राज्य में सक्रिय चरमपंथी समूहों के लोगों को हथियार डालने के लिये प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

विकास परियोजनाओं पर काम जल्दी शुरू करने तथा उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने से भी मणिपुर के लोगों का विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसे तमाम प्रयास मणिपुर के आहत लोगों की विश्वास बहाली में मददगार साबित हो सकते हैं। निस्संदेह, इस बार केंद्र सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

पड़ोस के घटनाक्रम पर रहे पैनी नज़र

पुष्कर जैन

नेपाल में जेन ज़ी की हालिया हिंसक क्रांति अचंभित करने वाली थी। नेतृत्व से युवा तंग आ चुके थे। बहरहाल, नयी सरकार बनने तक पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को बतौर अंतरिम प्रधानमंत्री शपथ दिलाई गयी। इससे पूर्व दो अन्य पड़ोसी देशों के लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था कब्जाने के विरुद्ध इच्छाशक्ति दिखाई। भारत के लिए सबक है कि दक्षिण एशिया को ध्यान के केंद्र में रखे।पिछले हफ़्ते की शुरुआत में नेपाल में क्रांति इतनी अचानक, इतनी त्वरित और इतनी नाटकीय थी कि भारत तक अचंभित रह गया। जब पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली की सशस्त्र पुलिस ने युवा छात्र प्रदर्शनकारियों पर, जिनमें स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहने बच्चे भी शामिल थे, निर्ममता से गोलियां चलाईं, तो भारतीय अधिकारियों को तुरंत अहसास हो गया कि पुरानी व्यवस्था ढह रही है। वे तो 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओली की भारत यात्रा की तैयारियां कर रहे थे। वे स्तब्ध थे कि इससे एकदम पहले ही घटनाओं ने अचानक बड़ा मोड़ ले लिया।

भारत–नेपाल संबंधों की खासियत यह है कि यह इतना घनिष्ठ, इतना गहरा और अटूट है कि भारत के रिश्ते किसी अन्य देश के साथ इस जैसे नहीं हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ साल पहले तराई और भारत के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के बीच इस 'रोटी–बेटी' के रिश्ते को दिल्ली के अभिजात वर्ग को बताकर चौंका दिया था, लेकिन यह मुहावरा नेपाल और भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी उतना ही सच है। नेपाल के अभिजात वर्ग और सर्वहारा वर्ग– 'बाहुन' और 'छेत्री', पहाड़ों के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, और निचले एवं मैदानी इलाकों के अन्य जातियों के लोग – भारत में विवाह करते आए हैं या बसे हैं और काम करते हैं और भारतीय भी इसी तरह से वहां रहते–काम करते हैं। रिश्तेदारी के बंधन पीढ़ियों को नया रूप देते रहे। अगर आप पटना से जनकपुर तक गाड़ी से जाते हैं, तो खुली सीमा पार करते समय कोई भी आपकी तरफ दुबारा गौर तक नहीं करता।

आप दलील दे सकते हैं कि यह बात तो भारत के हर पड़ोसी के लिए भी सच है, कि जातीयता, धर्म और संस्कृति –भूगोल एवं संप्रभुता– दोनों से, परे होती हैं। निश्चित रूप से, यह उन तीन देशों के लिए विशेष रूप से सच है जिनके लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कब्जाने के विरुद्ध अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है– 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और अब नेपाल। इन सभी क्रांतियों में छोटे–बड़े अंतरों के बावजूद, मौलिक समानता अभेद है। लोग इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि वे उस नेतृत्व से तंग आ गए, जिन्हें उन्होंने वोट डालकर चुना था लेकिन वे उन्हें ही गले में फंदा डालकर मवेशियों की तरह हांकने लगे।काठमांडू में चीज़ें तेज़ी से बदलीं। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा चुकी है और संसद भंग कर दी गई है। तथापि, सत्ता के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे संकेत हैं कि नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेल—जिन्हें भारत–नेपाल विशेष संबंधों के चलते पिछले दिसंबर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना में 'ब्रदर जनरल' का मानद पद प्रदान किया गया था—अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहते हैं और संभवतः राजशाही समर्थक राजनेताओं के पक्ष में झुकाव रखते हैं।

श्रमशक्ति के बेहतर उपयोग से सधेंगे आर्थिक लक्ष्य

नये परिदृश्य की चुनौती

शुभम चौधरी

यदि हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान कर सकें तो औसत आयु और शारीरिक विकास में और सुधार संभव है।

भारत में आगामी जनगणना की घोषणा कर दी गई है, जिसमें जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। इस जातिवार जनगणना का उद्देश्य वंचित वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर उनके कल्याण के लिए प्रभावी नीतियां बनाना है। हालांकि, यदि इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण किया गया, तो इसके सामाजिक लाभ की बजाय केवल राजनीतिक नारों और वादों का शोर सुनाई देगा, जिससे वंचित वर्गों को वास्तविक लाभ मिलने की बजाय केवल निराशा ही हाथ लगेगी।

भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण जन्म और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पहले जहां कई शिशु उचित चिकित्सा के अभाव में पांच वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते थे, अब उनकी संख्या आधी रह गई है। साथ ही, औसत आयु बढ़कर अब 72 वर्ष हो गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यदि हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान कर सकें तो औसत आयु और शारीरिक विकास में और सुधार संभव है।भारत में लोगों को रियायती राशन तो मिल रहा है, परंतु उन्हें गुणवत्ता युक्त जीवन और रोजगार की गारंटी नहीं मिल पा रही है। इसका सीधा असर बच्चों के पोषण पर पड़ रहा है। नतीजतन, देश में कुपोषण की समस्या बनी हुई है, जिससे कुछ बच्चे छोटे कद के पैदा हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोटापा भी स्वास्थ्य के लिए चुनौती है। हालिया आंकड़े की वर्तमान में प्रजनन दर 1.9 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जबकि जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए न्यूनतम दर 2.1 प्रतिशत होनी चाहिए। इस संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर अभी भी 2.1 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह घटकर 1.6 प्रतिशत रह गई है। इसका सीधा अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में किशोर और युवा जनसंख्या की हिस्सेदारी धीरे–धीरे कम होती जाएगी, और वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा। इसके विपरीत, ग्रामीण भारत में यह असंतुलन अपेक्षाकृत कम देखने को मिलेगा।इस बदलाव का सामाजिक और भौतिक ढांचे पर भी असर दिखने लगा है। शहरी क्षेत्रों में अब वृद्धजनों के अनुकूल रहन–सहन की मांग बढ़ रही है। इसलिए नियोजित फ्लैट, वृद्धाश्रम, और ऐसी बस्तियों का निर्माण बढ़ रहा है जहां बुजुर्ग सुरक्षित और सहज जीवन व्यतीत कर सकें।यदि यह गिरती हुई प्रजनन दर बनी रहती है, तो आने वाले वर्षों में भारत की कार्यशील जनसंख्या में कमी आ सकती है। तब भारत को एक युवा देश कह पाना कठिन होगा। जिस प्रकार हम जापान और चीन के बारे में कहते हैं कि वहां वृद्धजन अधिक और युवाजन घटते जा रहे हैं, भारत के शहरी क्षेत्रों में भी यह स्थिति उभर सकती है, खासकर तब जब परिवार नियोजन पर अत्यधिक बल दिया जाए।

साथ ही जनसंख्या परिवर्तन का राजनीतिक उपयोग भी देखा जा रहा है। कुछ वर्गों द्वारा इन आंकड़ों को अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे जनसंख्या नीतियों का संतुलन बिगड़ने की आशंका है।दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु से यह स्वर उभरा है कि वहां के लोगों ने समय रहते परिवार नियोजन अपनाया, जबकि उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश–बिहार इस दिशा में अपेक्षाकृत पीछे रह गए। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में जनसंख्या वितरण असंतुलित हो गया है। अब जब जनसंख्या के आधार पर संसदीय प्रतिनिधित्व तय होता है, तो दक्षिण भारत को आशंका है कि कम जनसंख्या के कारण उन्हें नुकसान हो सकता है।लेकिन विडंबना है कि आधुनिकता के दावों के बावजूद भारत में महिलाओं को रोजगार और उन्नति के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। केवल सीमित प्रतिशत में महिलाएं ही औपचारिक कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि शेष घरेलू या खेतों में कार्यरत हैं, जिनका श्रम अक्सर अनदेखा रह जाता है।

शिक्षकों को नज़रअंदाज़ करना समाज के लिए घातक

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शिक्षा को समाज का आधारस्तंभ कहा जाता है, लेकिन वही शिक्षक जो आने वाली पीढ़ी को गढ़ते हैं, आज सबसे अधिक उपेक्षा और अविश्वास का शिकार हो रहे हैं। देशभर में शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों को मूल्य, विवेक और जीवन जीने की समझ भी देते हैं। इसके बावजूद शिक्षकों को अक्सर राजनीतिक खेमों में बांटने की कोशिश की जाती है।

स्थिति यह है कि शिक्षण जैसे पवित्र पेशे को भी विचारधाराओं के चश्मे से देखा जाने लगा है

शिक्षक संगठनों का कहना है कि लगातार बदलती नीतियां, असमान वेतनमान, ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, और राजनीतिक दबाव शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। स्थिति यह है कि शिक्षण जैसे पवित्र पेशे को भी विचारधाराओं के चश्मे से देखा जाने लगा है। इससे न केवल शिक्षक की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सीधा असर पड़ता है।

शिक्षकों का कहना है कि उनकी भूमिका किसी पार्टी या विचारधारा का प्रचार करने की नहीं, बल्कि छात्रों को स्वतंत्र सोच, प्रश्नवृत्ति और न्याय-सत्य जैसे मूल्यों से जोड़ने की है। मगर जब उन्हीं की विचारधारा को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगे या प्रशासनिक

दवाब में उन्हें मोहरा बनाया जाए, तो यह शिक्षा की आत्मा पर प्रहार है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और समाज वाकई शिक्षा सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से समझना होगा। उन्हें उचित सम्मान, सुरक्षित वातावरण और नीति-निर्माण में भागीदारी मिले।

क्योंकि जब शिक्षक स्वतंत्र और सम्मानजनक माहौल में काम करेंगे तभी वे छात्रों को आत्मनिर्भर और मूल्यनिष्ठ नागरिक बना सकेंगे।

सार यही है कि शिक्षकों को राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देने वाला मार्गदर्शक समझना होगा।

एडीजी बंगले के पास बदमाशों का तांडव, महिला से जेवर-नकदी की लूट

» नीली अपाचे सवार तीन बदमाशों ने की मारपीट, बैग व मोबाइल छीनकर फरार

» बैग में थे सोने-चांदी के जेवर और 12 हजार नकद, पीड़िता ने दी तहरीर

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जहां एक ओर कानपुर पुलिस अपने सख्त रुख और लगातार चल रही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेश में ख्याति प्राप्त कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने एडीजी बंगले के सामने भी लूट की वारदात को अंजाम देने में कोई डर नहीं महसूस किया। बीती रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच नीतू राजपूत नाम की महिला अपने बेटे के साथ स्कूटी से घर लौट रही थीं। तभी नीले रंग की अपाचे बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उनकी स्कूटी को ओवरटेक कर रोक लिया और छीना-झपटी करने लगे।

महिला के विरोध करने पर लुटेरों ने धक्का देकर उन्हें और उनके बेटे को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने मारपीट करते हुए महिला के हाथ से बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए।

पीड़िता के अनुसार बैग में सोने की जंजीर, मंगलसूत्र, दो अंगूठियां, दो टॉप्स, चांदी की पायल, 12 हजार रुपये नकद, आधार कार्ड और मोबाइल फोन मौजूद था।

घटना एडीजी बंगले और सेदरलैंड के बीच की सड़क पर हुई, जो वीआईपी जोन माना जाता है।महिला ने कोतवाली थाने में प्रार्थना पत्र देकर मामले की शिकायत की है पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने दावा किया है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि, एडीजी बंगले के पास हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

काशी ज्वैलर्स को मिला वर्ष 2025 का सबसे शानदार स्टोर राष्ट्रीय पुरस्कार

यह पुरस्कार काशी ज्वैलर्स के वाइस प्रेसिडेंट श्रेयांश कपूर को प्रदान किया गया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।कानपुर की शान कहे जाने वाले काशी ज्वैलर्स को वर्ष 2025 का सबसे शानदार स्टोर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान इंडियन नेचुरल डायमंड रिटेलर्स एलायंस द्वारा दिया गया। इस अवसर पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और रॉयल राइजिंग ज्वेल्स ने भी सहभागिता की।यह पुरस्कार काशी ज्वैलर्स के वाइस प्रेसिडेंट श्रेयांश कपूर को प्रदान किया गया। यह सम्मान काशी ज्वैलर्स की अद्वितीय सोच, भव्यता और ग्राहकों को दी जाने वाली सर्वोत्तम सेवाओं का प्रमाण माना गया। ज्वैलरी हाउस ने पारंपरिक और आधुनिकता का खूबसूरत मेल अपनी अनूठी कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसने उद्योग में इसे एक अलग पहचान दिलाई।सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री श्रेयांश कपूर ने कहा, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि हमारे ग्राहकों और शुभचिंतकों के लगातार प्रेम, विश्वास और समर्थन से ही संभव हो सकी है। उन्होंने अपनी पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबके सामूहिक प्रयास और लगन से काशी ज्वैलर्स निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिये ठगी का धंधा, गिरोह का भंडाफोड़

- पुलिस ने आठ सदस्यों को पकड़ा, सरगना सुल्तान मिर्जा अब भी फरार
- टेलीग्राम-डार्क वेब से फंसाते थे लोग, करोड़ों का लेनदेन उजागर

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

3.25 हजार सैलरी और फ्री रहना-खाना, अपार्टमेंट से चलता था गैंग का नेटवर्क

कानपुर।बर्रा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग एप और वेबसाइट के जरिये लोगों को ठगने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस कार्रवाई में गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि सरगना अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मिर्जा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपितों के पास से 22 मोबाइल फोन, 3.21 लाख रुपये नकद, सात एटीएम कार्ड, एक कार और तीन बाइकें बरामद की गई हैं।

पुलिस के अनुसार गिरोह ऑनलाइन बेटिंग एप जैसे कार्तिकेय 365, लोटस 365 एक्सवाइजेड, रेडी बुक और दुबई ईएक्सएच के जरिए भोले-भाले लोगों को जाल में फंसाते थे। लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर धीरे-धीरे उनके भरोसे पर कब्जा जमाते और फिर बड़ी रकम लगवाकर सब कुछ हड़प लेते थे। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि गिरोह का नेटवर्क न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों तक फैला हुआ है।

टेलीग्राम और डार्क वेब से जाल

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित टेलीग्राम ग्रुप और डार्क वेब प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते थे। शुरुआत में छोटी-छोटी रकम जीताकर पीड़ितों को विश्वास दिलाया जाता कि गेमिंग बेट साइट से वह बड़ी रकम कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति लालच में आकर मोटी रकम लगाता, उसे सुनियोजित तरीके से हरवा दिया जाता और उसकी रकम पूरी तरह से हड़प ली जाती। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की ठगी से कई लोग कर्ज और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या तक कर चुके हैं, जबकि कई पीड़ित डर और शर्म के कारण सामने भी नहीं आ रहे हैं।

पकड़े गए आरोपितों के मोबाइल और लैपटॉप से हजारों फर्जी बैंक खाते और ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि केवल तीन महीनों में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है। बरामद खातों में से अभी तक 52 लाख रुपये की पहचान की गई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपितों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी गहन जांच शुरू कर दी गई है।

सैलरी पर काम करता था नेटवर्क

पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि गिरोह का स्थानीय नेटवर्क सिद्धार्थ विश्वकर्मा नामक युवक देखता था। बताया जाता है कि वह बीसीए की पढ़ाई के दौरान ही सरगना अभय शुक्ला के संपर्क में आया और धीरे-धीरे उसका दायां हाथ बन गया। सिद्धार्थ ने बाकायदा गिरोह में काम करने वालों को नौकरी की तरह सैलरी पर रखा था।

प्रत्येक सदस्य को महीने के 25 हजार रुपये वेतन मिलता था और रहने-खाने की सुविधा भी फ्री दी जाती थी। इसके लिए रतनलाल नगर स्थित हैप्पी टावर अपार्टमेंट किराए पर लिया गया था, जहां से गिरोह का पूरा ठगी का कारोबार संचालित होता था।

पूछताछ में सिद्धार्थ ने माना कि वह बीते छह महीनों से सक्रिय रूप से सरगना के लिए काम कर रहा था और पूरी टीम का संचालन करता था।

पुलिस ने बताया कि गिरोह के पास से मिले एटीएम कार्ड भी फर्जी नामों पर थे, जिन्हें आरोपितों ने किराए पर ले रखा था। इन खातों से करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन होता था और बदले में खाताधारकों को मामूली रकम दी जाती थी। यह संगठित नेटवर्क सुनियोजित ढंग से काम करता था, जिससे इसकी जड़ें कई राज्यों तक फैली हुई हैं।

कार्यालय में तहसीलदार सदर (न्यायिक) से मारपीट

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। तहसीलदार सदर (न्यायिक) की कोर्ट में दाखिल खारिज मामले में पैरवी करने पहुंचे एक युवक को फोन पर बात करने से मना करना तहसीलदार न्यायिक कैलाश नाथ यादव को महंगा पड़ गया। युवक ने न सिर्फ गालीगलौज की बल्कि मारपीट भी की। वहीं, कोर्ट में रखी चार वाद पत्रावलियों को फाड़ दिया। युवक ने तहसीलदार न्यायिक को जान से मारने की

धमकी भी दी। तहसीलदार न्यायिक (सदर) कैलाश यादव ने बताया कि इस मामले में एसडीएम सदर को जानकारी देने के साथ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। कानपुर तहसील परिसर स्थित तहसीलदार सदर (न्यायिक) की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दोपहर 1.20 बजे लालजी बनाम रामचंद्र मामले की सुनवाई चल रही थी। तहसीलदार सदर न्यायिक ने बताया कि इसी बीच लालजी के साथ पैरोकारी करने आए दबौली निवासी विजय शंकर मिश्रा कोर्ट के सामने ही तेज आवाज में मोबाइल पर बात करने लगे। कोर्ट की सुनवाई में बाधा होने पर उन्हें बाहर जाकर बात करने के लिए कहा तो वह गालीगलौज कर मारपीट पर आमादा हो गया। मोबाइल छीन लिया। साथ ही, धारा 67 की 4 वाद पत्रावलियों को फोड़ दिया और गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।

सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की माँग तेज

» राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने पीएम को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा

» हजारों शिक्षकों ने रैली निकालकर लगाई नारेबाजी, निर्णय को बताया सेवा-सुरक्षा पर संकट

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उच्चतम न्यायालय के 1 सितम्बर 2025 के निर्णय के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों में आक्रोश है। न्यायालय ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है, चाहे उनकी नियुक्ति तिथि कोई भी क्यों न रही हो।

इस फैसले के विरोध में सोमवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले हजारों शिक्षक-शिक्षिकाएं माती ओवरब्रिज के नीचे जुटे और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

रैली का नेतृत्व कर रहे प्रदेश महामंत्री प्रदीप कुमार तिवारी ने बताया कि महासंघ के आह्वान पर 15 सितम्बर को पूरे देश के 780 जनपदों से एक साथ प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ला ने कहा कि यह निर्णय लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और आजीविका पर सीधा हमला है।

जिला महामंत्री सुनील सचान ने मांग रखी कि टीईटी की अनिवार्यता को केवल भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही लागू किया जाए।

जिला कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि वैध नियमों के तहत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों को सेवा से हटाना या उनकी जीविका पर संकट खड़ा करना न्यायसंगत नहीं है। महिला संवर्ग की जिलाध्यक्ष ज्योत्सना गुप्ता ने आश्वस्त किया कि संगठन हर शिक्षक की सेवा-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर संगठन मंत्री अनंत त्रिवेदी, डॉ. इंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, पुनीता पालीवाल, संत कुमार दीक्षित, अजय गुप्ता, देवेंद्र तिवारी समेत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शिक्षक मौजूद रहे।

सभी ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि इस निर्णय को वापस लिया जाए और सेवारत शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए।

डीएम की सख्ती से संवरने लगी निनाया गौशाला

» मवेशियों को समय पर हरा चारा और स्वच्छ पानी की व्यवस्था

» अधिकारी कर रहे हैं नियमित निरीक्षण, साफ-सफाई पर खास जोर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। डीएम कपिल सिंह की सख्ती का असर अब जिले की गौशालाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक अंतर्गत शाहजहांपुर निनाया में बनी गौशाला में मवेशियों को समय-समय पर स्वच्छ पानी और हरा चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले यहां व्यवस्थाओं की अनदेखी होती थी, लेकिन अब हालात तेजी से सुधर रहे हैं। एडीओ पंचायत वीरेंद्र पाल और ग्राम पंचायत अधिकारी दीपक यादव नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं

और हर दिशा-निर्देश का पालन कराया जा रहा है।ग्राम पंचायत अधिकारी दीपक यादव ने बताया कि उनकी प्राथमिकता गौशाला की साफ-सफाई और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा समय-समय पर दवाइयों का छिड़काव भी कराया जाता है, ताकि संक्रमण से मवेशियों को बचाया जा सके। यदि इसी तरह जिले की अन्य गौशालाओं में भी काम किया गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'सुव्यवस्थित गौशाला' का सपना हकीकत में बदल सकता है।

हाईवे बना मौत का जाल, 25 किमी सफर हर कदम पर खतरा

» सड़क सुरक्षा समिति में मुद्दा उठने के बाद भी जिम्मेदार बने लापरवाह

» गड्ढों और बारिश के पानी से आए दिन हादसों का शिकार हो रहे वाहन सवार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो,

कानपुर देहात।झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे का पिपरी भोगनीपुर से लेकर बारा जोड़ तक का 25 किलोमीटर का सफर लोगों के लिए जानलेवा बन चुका है। हाईवे पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और दब चुकी सड़कें वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। दोपहिया और चारपहिया सवारों को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी चूक होते ही हादसा तय है।कई बार मांग उठने और सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में मामला आने के बावजूद एनएचएआई और जिम्मेदार अधिकारी अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। सबसे खराब हालात कानपुर की ओर जाने वाले लेन की है, जहां पिपरी, भोगनीपुर, पुखराया, हासेमऊ डींघ, देवीपुर, मावर और लालपुर के पास कई बड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं।रात का अंधेरा और हल्की बारिश स्थिति को और भयावह बना देते हैं। बारिश में गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से मरम्मत की मांग कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन और एनएचएआई की उदासीनता मौतों को दावत दे रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 । **Email:** swarajindia2023@gmail.com । **Mob:** 7800009853, । **Website:** www.swarajindianews.com । (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

दो दिन से लापता नाबालिग बहनें, पुलिस के हाथ अब भी खाली

» जंगल में लकड़ियां बीनने गईं थीं 12 और 7 साल की मासूम बहनें

» सर्विलांस और एसओजी समेत कई टीमें तलाश में जुटीं, पर सुराग न मिला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।गजनेर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह लकड़ियां बीनने जंगल गईं दो सगी बहनें 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका। मामला रतवा मौजा नाही जूनिया गांव का है, जहां धर्मेंद्र कुमार की बेटियां लक्ष्मी (12) और प्रीति (7) घर से जंगल गई थीं, लेकिन लौटकर नहीं आईं। जब काफी देर तक दोनों नहीं पहुंचीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, पर नाकाम रहे। इसके बाद गांव

स्वराज इंडिया
कानपुर देहात
09
जंगल में लकड़ियां बिनने गईं दो मासूम बहनें लापता

के ही धर्मेंद्र नामक युवक ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह ने पुलिस टीम के साथ गांव, जंगल, खेतों और आसपास के संभावित स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। बावजूद इसके दोनों का कहीं पता नहीं चल सका। देर रात तक घर न लौटने पर सुजातगंज कानपुर नगर में काम करने वाले पिता धर्मेंद्र कुमार भी गांव पहुंच गए। मां मीना देवी ने दोनों बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। जांच में यह सामने आया कि किशोरियों का भाई हिमांशु (16) बीते शुक्रवार से ही सुजातगंज से लापता था। बहनों ने मां से अपने भाई को खोजने की बात कही थी। चश्मदीदों ने बताया कि दोनों किशोरियों को रेलवे लाइन किनारे तिलोंची स्टेशन की ओर जाते देखा गया था। इस आधार पर पुलिस को शक है कि वे कानपुर नगर की ओर गई होंगी।

पुलिस ने किशोरियों की तलाश के लिए रात में ही पंपलेट तैयार कराकर जीआरपी, आरपीएफ और आसपास के जिलों की पुलिस को सूचना भेज दी।

सोशल मीडिया पर भी बच्चियों की जानकारी साझा कराई गई। चौकी प्रभारी पामा अमरेंद्र प्रताप सिंह और ग्रोथ सेंटर प्रभारी सुनील सिसोदिया के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सर्विलांस व एसओजी टीमों को भी लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि हर संभव प्रयास जारी हैं और दोनों मासूम बहनों को जल्द बरामद कर लिया जाएगा।

गुजरात से लौटा युवक नीम के पेड़ पर झूला, गांव में सनसनी

» सिहारी गांव में खेत के पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव

» मौत का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस जांच में जुटी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मूसानगर थाना क्षेत्र के सिहारी गांव में सोमवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव का एक युवक खेत में खड़े नीम के पेड़ पर फंदे से लटकता मिला।

परिजनों और ग्रामीणों ने आनन-फानन उसे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।सिहारी गांव निवासी शिव सिंह ने बताया कि उसका 30 वर्षीय भतीजा रोहित गुजरात की एक निजी कंपनी में काम करता था और कुछ दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। सोमवार शाम वह खेत की ओर गया था, जहां उसने पैंट और शर्ट को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर नीम के पेड़ की डाल से फंदा लगाकर जान दे दी।

शव को देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने उसे नीचे उतारा और तुरंत पुखरायां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इमरजेंसी चिकित्सक डॉ. आरती सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मूसानगर थानाध्यक्ष कालीचरण कुशवाहा ने बताया कि युवक की आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन रो-रोकर बेहाल हैं।

रोटावेटर की चपेट में आने से युवक की मौत, लापरवाही पर उठे सवाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में मंगलवार को खेत में काम करते समय हुई एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। खेत में रोटावेटर चलाते समय 35 वर्षीय युवक विक्रम उर्फ विनय प्रताप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसे साफ लापरवाही का नतीजा बताया है।सूत्रों के मुताबिक, ट्रैक्टर गांव के ही मोहर सिंह चला रहे थे। इसी दौरान विक्रम मशीन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि उसका शव रोटावेटर में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया।

घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में काम के दौरान सुरक्षा नियमों और सावधानियों की अनदेखी की जाती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं।

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि खेतों में भारी मशीनों के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते। लापरवाही का यह नतीजा एक परिवार की खुशियां छीन ले गया।

स्कूल वालों ने हमाई बिटिया को मार डाला...!

ओंकारेश्वर सरस्वती स्कूल के टीचर्स के तनाव से नौवीं की छात्रा ने किया सुसाइड

» आस्था और अनुशासन की टकराहट, मासूम ने गंवाई जिंदगी

» शिक्षिका की फटकार बनी जानलेवा, छात्रा ने ट्रेन से कटकर दी जान

» स्वजन बोले शिक्षिका और प्रबंधन की सख्ती ने ली मासूम की जान

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जवाहर नगर स्थित ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली नौवीं की छात्रा संस्कृति ने सोमवार को ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। रावतपुर थानाक्षेत्र के आवास विकास केशवपुरम निवासी मुकुल आनंद की 13 वर्षीय बेटी सुबह गणेश प्रतिमा लेकर स्कूल गई थी। आरोप है कि कक्षा में प्रतिमा देखने पर शिक्षिका ने उसे फटकार लगाई और मां साधना को तुरंत स्कूल बुला लिया।

स्वजन के मुताबिक शिक्षिका और प्रबंधन ने न सिर्फ छात्रा को डांटा बल्कि उसकी मां से लिखित प्रार्थना पत्र भी लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बच्ची मानसिक रूप से बेहद आहत हुई। छुट्टी के समय जब सभी छात्र-छात्राएं घर लौटे, संस्कृति ने घर का रुख करने के बजाय गोल चौराहे की ओर कदम बढ़ाए और रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने कूद गई। पुलिस ने बैग से मिले आइकार्ड और कागजात से उसकी पहचान की और स्वजन को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो रो-रोकर उनका बुरा हाल हो गया। स्वजन ने साफ तौर पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षिका को बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया है।

विद्यालय प्रबंधन बोला

विद्यालय प्रबंधन ने इस घटना पर दुख जताते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रधानाचार्य राममिलन सिंह का कहना है कि छात्रा छुट्टी के बाद अपनी मां के साथ घर के लिए निकली थी। इसके बाद उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी विद्यालय को नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दु:खद घटना है, जिससे पूरा विद्यालय परिवार स्तब्ध है और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

केडीए के जमीनों पर कब्जों पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की जमीन मुक्त

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जोन 4 में करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई गई

कानपुर। शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) का शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर रत्तूपुरवा में ज़ोन-4 प्रवर्तन दस्ता प्रभारी प्रवीण शर्मा की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई।

भूखंड संख्या 326 और 327 पर अवैध कब्जा कर लोग निर्माण कर रहे थे। जब केडीए टीम ने कागज़ मांगे तो कोई वैध दस्तावेज़ नहीं दिखा पाए। विरोध करने पर पुलिस फोर्स ने मौके से लोगों को खदेड़ा और बैकहो लोडर से निर्माण गिरा दिए।इसके अलावा क्षेत्र के दो और भूखंडों पर कब्जे की पुष्टि होने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अगले हफ्ते इन जगहों पर भी कार्रवाई की जाएगी।केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्यांयाल ने साफ निर्देश दिए हैं कि सील की गई इमारतों में अगर दोबारा काम मिलता है तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो। नक्शे के विपरीत निर्माण और अतिरिक्त छत डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। पुरानी योजनाओं का सर्वे कर अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें खत्म किया जाए। कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अमरनाथ यादव सहित स्थानिक पुलिस और केडीए के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

अयोध्या एयरपोर्ट के घटिया निर्माण की बारिश से खुली पोल

» जनता बोली कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फव्वारे का स्वागत-विकास या लापरवाही?

» यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

» इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसे रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं और विदेशी यात्रियों के लिए भव्य द्वार बताया गया था, बरसात की पहली बूंदों में ही ध्वस्त नज़र आया। डिपार्चर डी1 और डी2 के सामने की छत से बारिश के पानी की धाराएं बहने लगीं। करोड़ों रुपये की लागत से बनी छत देखते-देखते फव्वारे में तब्दील हो गई।

प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर छत के नीचे ही भीगना पड़ा। एयरपोर्ट प्रबंधन और निर्माण एजेंसी ने तमाशा देखते हुए जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। एक यात्री की नाराज़गी फ्रहमने सोचा था रामलला के दरबार में श्रद्धा की वर्षा होगी, मगर यहां तो एयरपोर्ट की छत ही बरसने लगी।

अयोध्या में विकास योजनाओं का हाल जगजाहिर है। कहीं सड़कों का डामर पहली ही बरसात में बह जाता है। कहीं फुटपाथ उखड़ जाते हैं। कार्यदाई संस्थाओं पर आरोप है कि उन्होंने निर्माण के नाम पर जेबें भरीं और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया।

एयरपोर्ट की साख पर धब्बा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या की पहचान के लिए बनाया गया एयरपोर्ट अब शर्मिंदगी का कारण बन रहा है। क्या यह यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं?क्या सरकार ने निर्माण एजेंसियों को बिना जांच-परख के काम सौंपा? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा?

स्वराज इंडिया का सवाल

अयोध्या में विकास के नाम पर हो रहे कामों में बार-बार खामियां क्यों मिल रही हैं? क्या करोड़ों की योजनाएं सिर्फ ठेकेदारों और अधिकारियों की जेबें भरने का ज़रिया बन चुकी हैं?और सबसे बड़ा सवाल रामलला की नगरी में विकास का दिखावा कब तक यात्रियों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता रहेगा?

विनोद कुमार निदेशक-एयरपोर्ट

बरसात के बाद होगी मरम्मत-विनोद सिंह
डायरेक्टर एयरपोर्ट ऑथरिटी

महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद सिंह का कहना है कि यह बहुत खराब स्थिति है सामने की रोड और छत से पानी टपकने की समस्या को हमने प्राथमिकता से लिया है। बारिश के बाद इसका टेंडर होगा इसका एक प्रोसेस होता है जल्द ही उसे सही कर लिया जाएगा।

अवध विश्वविद्यालय में गूंजती गड़बड़घोटाला की कहानी

» अवध विश्वविद्यालय का कर्मचारी परिषद या कुर्सी परिषद?

» परिषद का कार्यकाल एक साल का लेकिन चुनाव दो साल बाद भी नही

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।अवध विश्वविद्यालय के कर्मचारी परिषद पर इस समय सवालों के बादल गहराए हुए हैं। हालात ऐसे कि परिषद के महामंत्री ने अपने निधन से पूर्व ही इस्तीफा सौंप दिया। उनके बाद उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, मीडिया प्रभारी समेत तमाम पदाधिकारियों ने भी सामूहिक त्यागपत्र दे डाला। नियमों के मुताबिक परिषद का स्वतः भंग होना तय था, मगर हकीकत उलटी है।

सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी परिषद आज भी एक ऐसे अध्यक्ष की गिरफ्त में है, जो कुर्सी को छोड़ने को तैयार ही नहीं। नाम है— राजेश पांडेय। वही राजेश पांडेय जो सालों से परीक्षा विभाग के प्रभारी की कुर्सी से चिपके हुए हैं। अब कर्मचारी परिषद की गद्दी पर भी मानो फेविकोल लगा कर बैठे हों। बता दे कि परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल महज एक साल का होता है, मगर दो साल से चुनाव ही नहीं कराए गए। परिणाम यह कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप्प पड़ी है और परिषद एक व्यक्तिगत कुर्सी परिषद बनकर रह गई है।

विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद की कहानी अब सवाल पूछती है की

क्या परिषद लोकतंत्र की मिसाल है या कुर्सी प्रेम का अखाड़ा? क्या इस्तीफों के बाद परिषद का भंग होना चाहिए था? आखिर चुनाव कराने से कौन-सी ताकतें रोक रही हैं? अवध विश्वविद्यालय की गलियारों में आज बस एक ही चर्चा है। परिषद नहीं, कुर्सी परिषद बचाने की जुगत चल रही है।

एनसीटीई पर लगाया शपथपत्र में अंतर्विरोध का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) अयोध्या के मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह ने एनसीटीई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर 5 मार्च 2025 के शपथपत्र को विरोधाभासी बताया है। उनका कहना है कि बिंदु 11 में एनसीटीई ने 2001 से 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट स्वीकार की है, जबकि बिंदु 13 में इन्हीं शिक्षकों पर टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता थोप दी गई है।

बलबीर सिंह का आरोप है कि यह विरोधाभास न सिर्फ नीतिगत असंगति है, बल्कि लाखों शिक्षकों के बीच भ्रम और असुरक्षा भी पैदा कर रहा है। उन्होंने अदालत और सरकार से इस पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है।

गाजीपुर प्रकरण: थाने में पिटाई से गई भाजपा कार्यकर्ता की जान, नहीं मिला न्याय

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गाज़ीपुर/लखनऊ। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे न्याय नहीं चाहिए... यहाँ सब भ्रष्ट हैं। मेरे भाई की हत्या को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ले जाओ 10 लाख जो दिया है...यह शब्द हैं मृतक सियाराम उपाध्याय के बड़े भाई के, जिनकी आँखों में सिर्फ़ आंसू और दिल में गहरा आक्रोश है।12 सितंबर को नोनहरा थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में बंद कर बेरहमी से पिटाई की, जिससे दिव्यांग सियाराम ने दम तोड़ दिया। हाथ-पैरों पर चोटों के निशान, लाठीचार्ज की बर्बरता का दर्दनाक सबूत बने हुए हैं।

9 सितंबर 2025 को रुकूनुद्दीनपुर गाँव में बिजली के खंभे को लेकर प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच विवाद हुआ। इसी को लेकर 20-25 ग्रामीण थाने पहुंचे थे। परिजनों का कहना है कि उसी दौरान पुलिस ने लाइट बंद कर निर्दोष लोगों पर डंडे बरसाए, जिसमें सियाराम बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त उनकी साँसें थम गईं।

मृतक के भाई का कहना है–

सच्चाई को दबाने के लिए पुलिस हमारी पीड़ा को हार्ट अटैक का नाम दे रही है। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ सब बिक चुका है।

» न्याय की आस में भटक रहा परिवार, सीएम योगी से मिले परिजन

न्याय न मिलने को लेकर मीडिया को जानकारी देते परिजन

सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुचे मृतक सियाराम उपाध्याय के पिता वा भाई शशिकांत उपाध्याय साथ ही उनके वहाँ गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल भी मौजूद रहे । निष्पक्ष जांच का मिला आश्वासन।

न्याय की उम्मीद और बढ़ रही मायूसी

पीड़ित परिवार स्थानीय विधायक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिला।

सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा। परिजनों का कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस की लापरवाही ने लोगों के दिलों से न्याय की उम्मीद छीन ली है।

गांव के लोग स्तब्ध हैं। किसी के घर का बेटा, किसी का भाई, किसी का सहारा अब सिर्फ़ तस्वीरों में रह गया।

गोरखपुर में NEET अभ्यर्थी की हत्या

» पशु तस्करों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

» यूपी में हत्याये बढ़ने से लोगों में गुस्सा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर शहर में दिल दहला देने वाली वारदात ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ह्श्वश्वञ्ज की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तस्करों ने दीपक को एक घंटे से अधिक समय तक अपने कब्जे में रखकर घुमाया और बाद में उसके मुंह में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर गाड़ी फंकी और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर देर से पहुंची, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। CM के निर्देश पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से संवाद किया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल पुलिस टीम ने इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी है और पशु तस्करों की तलाश तेज कर दी गई है। इस जघन्य हत्या से इलाके में आक्रोश और भय का माहौल व्याप्त है।

गोरखपुर एसएसपी का बयान पढ़िए

गोरखपुर एसएसपी राज करण नैय्यर ने बताया,पिपराइच थाना क्षेत्र में सुबह 3 बजे एक गांव में पशु तस्कर 2 गाड़ियों में आए थे जिनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे तस्कर भाग निकले। दूसरी गाड़ी का गांव के एक युवक के द्वारा पीछा किया गया। युवक के सिर पर चोट आई और उसकी मौत हो गई। सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज़ करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि गोली मारी गई है लेकिन प्रथम दृष्टया चोटों को देखने पर कोई गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। टीमें लगाई गई हैं, जल्द गिरफ़्तारी कर ली जाएगी।एक पशु तस्कर गांव वालों के हाथ लगा था जिसे चोटें आई हैं। जिसका इलाज कराया जा रहा है।